साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 15-21 जुलाई 2024 वर्ष-10, अंक-13
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-केंद्र सरकार का फैसला नाराज किसानों को करेगा खुश

पीएम के बजट पर टिकी देश के किसानों की नजर

दल-तिलहन पर 100% एमएसपी देने की तैयारी!

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में पीएम अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस योजना के तहत चुनिंदा दलहन और तिलहन की 100 फीसदी सीधी खरीद के जरिए या मूल्य में अंतर चुकाकर एमएसपी पक्का किया जा सकता है। इसका संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके हैं। हाल में चौहान ने कहा था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी राज्यों से अरहर, उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद एमएसपी पर किया जाए। दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले दलहन और तिलहन किसानों को एमएसपी देने के उद्देश्य से पीएम-आशा योजना शुरू की थी। इसमें किसान एक निश्चित मात्रा तक ही अपनी उपज ही बेच सकता है। पहले केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसी सीजन में हुई वास्तविक फसल का 25 फीसदी खरीदने के लिए बाध्य थी। लेकिन राज्य सरकार को 25 फीसदी से अधिक उपज खरीदना होती थी, तो सरकार को अपने पास से रकम लगानी पड़ती थी। बाद में केंद्र सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई। फिर केंद्र सरकार ने 2023-24 में अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40 फीसदी खरीद की सीमा हटा ली थी।

सीएसीपी भी दे चुका सलाह

हर साल 20 से ज्यादा फसलों के एमएसपी तय करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दलहन की सरकारी खरीद पर कोई बंदिश नहीं लगाने और तिलहन के दाम एमएसपी से नीचे जाने पर उस अंतर की भरपाई करने की सलाह दी है। सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद के लिए 40 फीसदी की जो सीमा 2023-24 में हटा ली गई थी, उसे अगले 2 से 3 सीजन के लिए बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य पक्का हो सके।

राज्यों का दायरा भी बढ़ेगा- योजना में बदलाव के बाद अगर बाजार में कीमत एमएसपी से कम हुई, तो दलहन और तिलहन किसानों की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्यों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं, योजना में बदलाव के बाद बाजार में दाम घटने पर किसानों की दलहन और तिलहन उपज दाम के अंतर के बराबर मुआवजा पाने की हकदार हो जाएगी, जो सरकार उन्हें देगी।

मूल्य सुनिश्चित करने के जरूरत

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ दशक में खाद्य तेलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। देश की 60 फीसदी जरूरत आयात से पूरी की जाती है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में तिलहन की खेती को बढ़ावा देने और पैदावार में सुधार लाने और तिलहन उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के जरूरत है। आयोग ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन का दायरा सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

सहायिकाओं को फिर मिलेगी भोजन बनाने की जिम्मेदारी

अब बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान

» मध्यप्रदेश में करीब 97 हजार से ज्यादा हैं आंगनबाड़ी केंद्र

» मध्यान्ह भोजन में अंचल की प्रसिद्ध पकवान जरूर परोसेंगे

» मिलेट्स में काफी पोषक तत्व होने से सेहत को होगा फायदा

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के 97 हजार 135 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में एक या दो दिन मोटे अनाज से बनी चीजें देने की तैयारी है। साथ ही हर अंचल में वहां की प्रसिद्ध और बच्चों के लिए रुचिकर चीजें दी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उस अंचल में प्रसिद्ध खाने की चीजों के आधार पर पूरे एक सप्ताह के भोजन का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल, केंद्र और प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है। इसका, बड़ा कारण इनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व हैं। कुपोषण और बीमारियों के कारण शून्य से छह वर्ष के उम्र के बच्चों में से 40 प्रतिशत ठिगनापन और 27 प्रतिशत कम वजन के हैं। इनमें कुछ बच्चे ठिगनापन और कम वजन दोनों के शिकार हैं। इस कारण पोषण आहार में बदलाव की तैयारी है।

आंगनबाड़ी सहायिका बनाएगी भोजन

दूसरा परिवर्तन यह किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम स्व-सहायता समूह की जगह आंगनबाड़ी सहायिका को देने पर विचार चल रहा है। पहले भी सहायिका के पास यह जिम्मेदारी थी। कुछ वर्षों से यह काम स्व-सहायता समूहों को दे दिया गया था। सहायिका आंगनबाड़ी की ही कर्मचारी हैं, इसलिए विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वह भोजन बनाने की जिम्मेदारी और अच्छे से संभाल सकती हैं। हालांकि, स्व-सहायता समूह इसका विरोध कर रहे हैं।

मोटे अनाज से बनी चीजों को आंगनबाड़ी केंद्रों के भोजन में शामिल करेंगे। यह भी प्रयास किया जा रहा है जिस अंचल में खाने की जो चीज ज्यादा प्रसिद्ध है, बच्चे अपने घरों में उन्हें खाते हैं। उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दिया जाएगा।
- निर्मला भूरिया मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग

-सीएम ने कहा-स्कूलों में कृषि संबंधी विषयों का अध्ययन हो आरंभ

मप्र में 10वीं-12वीं के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी कृषि का पाठ

भोपाल। जागत गांव हमार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई आरंभ की जाए। प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिकांशतः खेती-बाड़ी की पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं। अतः इन विषयों पर पढ़ाई आरंभ करने से विद्यार्थियों का शालाओं से अधिक जुड़ाव होगा। अध्ययन-अध्यापन परिवार के लिए अधिक उपयोगी बन सकेगा। सीएम राइज स्कूलों में इन विषयों की पढ़ाई प्राथमिकता पर आरंभ की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं में संकाय व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थियों को अपनी रुचि व प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनने की व्यवस्था भी की जाए। यह व्यवस्था उच्च शिक्षा में लागू हो चुकी है, स्कूल स्तर पर यह व्यवस्था क्रियान्वित करने के लिए शिक्षाविदों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्था तथा विषय-विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सीएम राइज स्कूलों के संचालन की बैठक में उक्त निर्देश दिए। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा सहित अधिकारी उपस्थित थे।

-संकाय का बंधन न हो, विद्यार्थी रुचि और प्राथमिकता से चुनें विषय

-मोहन यादव ने सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश

हर विकासखंड में हो आईटीआई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण अंचल में प्राथमिकता के आधार पर सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जाएं। इन शालाओं में शिक्षकों व स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में भारत सरकार से भी सहायता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में एक आईटीआई स्थापित करने की दिशा में प्रयास हों, जिन विकासखंडों में आईटीआई नहीं है, वहां निजी क्षेत्र की पहल से सुविधा उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई जाए। आगामी इण्डस्ट्रियल समिट में भी इस दिशा में इच्छुक निवेशकों से चर्चा की जाए।

स्कूलों हो ई-व्हीकल्स का उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों की परिवहन व्यवस्था में ई-व्हीकल्स का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। नगरीय निकायों में बने सीएम राइज स्कूलों के विद्यार्थियों के आवागमन के लिए नगरीय निकाय की नगर वाहन सेवा के अंतर्गत चल रहे वाहनों का भी उपयोग किया जाए। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और सुविधाजनक विद्यालय आवागमन के लिए वाहनों के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।नवीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि के चिन्हांकन का कार्य परस्पर विभागीय समन्वय से समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। प्रकरणों में विलंब होने की स्थिति में उनका निराकरण राज्य स्तर से कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के आसपास कोई अतिक्रमण न हो।

मछुआ दिवस पर राज्यमंत्री ने मछुआरों को दी बधाई

प्रदेश में 3.42 लाख मीट्रिक टन हुआ मत्स्योत्पादन, जरूरतमंदों को रोजगार

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया गया। इस संबंध में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार ने मछुआरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मछली पालन को प्रोत्साहित कर बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश में 3 लाख 42 हजार मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया। मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में प्रदेश में 3 लाख 90 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। पंवार ने कहा कि नीली क्रांति से प्रदेश में आर्थिक क्रांति लाने के ठोस प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार मछली पालन के साथ-साथ उसके प्र-संस्करण, विपणन और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिये विशेष अभियान चालाया है। इस अभियान से उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा के मिलने से प्रदेश के मत्स्य पालक साहूकारों और बिचौलियों के हाथों से फँसने से बच सकें है।

2024-25 का रोडमेप तैयार- प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में विभाग ने रोडमेप तैयार किया है। रोडमेप के जरिये प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की नई संभावनाओं के लिए स्थानों को चिंन्हित किया जा रहा है। प्रकृतिक तालाबों एवं जल-संरचनाओं को मत्स्य पालन के अनुकूल बनाने के लिए विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे है।

-भोपाल में मनाया गया मछुआ दिवस

प्रदेश में बढ़ाया जा रहा मत्स्य उत्पादन

इधर, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी समिति परिसर में सचिव मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की उपस्थिति में मछुआ दिवस मनाया गया। प्रति वर्ष 10 जुलाई 1957 को डॉ. हीरालाल चौधरी द्वारा सीफा भुवनेश्वर में पहली बार सफर मछली का सफलता पूर्वक प्रजनन कराया गया था। यह एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य था, जिससे मछली पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इस क्रांति को नीली क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति से देश में लाखों लोगों को मछली पालन से जोड़ा गया है। इस उपलब्धि के लिये देश में हर साल 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया जाता है। मछुआ कलयाण सचिव डॉ. कोठारी ने कहा कि प्रदेश में मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास के लिये ठोस प्रयास किए जा रहे है। अधिक से अधिक मछुआरों को सहकारी समिति के दायरे में लाया जा रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश में 3 लाख 42 हजार मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया।

मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को किया हासिल

उन्होंने कहा कि मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में प्रदेश में 3 लाख 90 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। कार्यक्रम में संचालक मत्स्य उद्योग भरत सिंह और मुख्य महाप्रबंधक ज्योति टोप्पो ने भी संबोधित किया। ज्योति टोप्पो मुख्य महाप्रबंधक मत्स्य महासंघ द्वारा सभी मछुआ भाई बहनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि कोई भी कार्य बिना लक्ष्य के पूरा नहीं हो सकता हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना होता है। तालाबों से मत्स्य उत्पादन में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य लगातार प्रगति कर रहे हैं टोप्पो द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी मछुआ भाई बहनों की सराहना की। मछुआ दिवस के मौके पर प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मछुआरों को पुरस्कृत किया गया।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री ने भोपाल के नागरिकों को दी बधाई

एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधरोपण की पहल देश के लिए मिसाल

-अभियान मां की सेवा के पवित्र भाव को मजबूती प्रदान करेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पौधरोपण कर एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल के मेरे भाई-बहनों की यह पहल देश भर के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा सदैव देश का सामूहिक संकल्प बनकर जन सहभागिता के माध्यम से इतिहास रचती रही है। स्वच्छता अभियान से देश की तस्वीर बदलने से लेकर कोरोना को पराजित करने तक देश ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर विश्व के सामने अद्भुत मिसाल पेश की। निश्चित ही एक पेड़ मां के नाम अभियान भी देश में पर्यावरण संरक्षण के साथ मां की सेवा के पवित्र भाव को मजबूती प्रदान करेगा। मध्यप्रदेश ने 5.50 करोड़ पौधरोपण का संकल्प साकार करने का बीड़ा उठा लिया है।

12 लाख पौधे रोपे गए

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने जम्बूरी मैदान, भोपाल में पौधा रोपकर प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की। भोपाल में 300 जगह एक दिन में रिकॉर्ड 12 लाख पौधे रोपे गए। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या में पौध रोपण कर अभियान में योगदान किया।

अब मिनटों में फैल जाएगी खेत में गोबर की खाद

अब मिनटों में फैल जाएगी खेत में गोबर की खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

लगभग सभी किसान अपने खेतों में गोबर वाली खाद फैलाते हैं, लेकिन खेत में खाद फैलाते वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती होती है इसे समान रूप से फैलाना। जब भी ट्रॉली में भरकर खेत में खाद डाला जाता है तो एक तो इस काम में मजदूर लगाने पड़ते हैं लेकिन फिर भी खाद समान रूप से खेत में नहीं फैल पाता है। किसानों की इसी समस्या का समाधान है कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन। हम अपने पाठकों को इसी कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही इसकी कीमत और सब्सिडी के बारे में भी बताएंगे।

क्या होती है कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन - ये असल में एक ट्रैक्टर इम्पलीमेंट है जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है। यह मशीन समान अनुपात में खेत में खाद फैलाती जाती है, जिससे खाद बरबाद भी नहीं होती और किसान की मेहनत भी बचती है। कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन भी कई तरह की होती हैं, जिनमें एक पंखा वाली कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन होती है। ये सीधे-सीधे गोबर या खाद के ढेर को अपने बड़े पंखों से फैलाती है। वहीं एक दूसरी तरह की मशीन होती है जिसमें खुद एक छोटा टैंकर होता है। इस टैंकर में खाद भरी जाती है और ट्रैक्टर के पीछे लगी ये मशीन खेत में खाद बिखेरती हुई जाती है।

वहीं एक तीसरे तरह की ट्रॉली वाली कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन होती है। ये मशीन बड़े स्तर पर खाद फैलाने के काम आती है। इस तरह की कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन एक बड़ी ट्रॉली के पीछे लगी होती है जो डायरेक्ट ट्रॉली में भरे खाद को ही अपने पंखों से खेत में बिखेरते हुए चलती है। हालांकि सबसे ज्यादा टैंकर वाली कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन ही उपयोग में आती है।

कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन के फायदे

खाद फैलाने वाली इस मशीन के कई सारे फायदे हैं। इस मशीन से सिर्फ गोबर की खाद ही नहीं बल्कि रासायनिक उर्वरक भी खेत में डाला जा सकता है। यह मशीन ट्रैक्टर में लगाकर चलती है इसलिए कुछ ही मिनटों में एक बीघा खेत में अच्छे से खाद फैला सकते हैं। किसान कितनी मोटी और पतली परत में खाद फैलाना चाहते हैं, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए इस मशीन में हाइड्रोलिक मोटर से जुड़ी हुई एक जॉय स्टिक लगी होती है, जिससे इसका ऑपरेशन कंट्रोल होता है। इतना ही नहीं खेत में खाद फैलने वाली परत की मोटाई और मशीन की रफ्तार ट्रैक्टर की गति के साथ सिंक की जा सकती है। इसके साथ ही खाद फैलाने की परत की चौड़ाई अलग-अलग तरह से समायोजित या विभाजित की जा सकती है। कुछ कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन की खाद लोडिंग की क्षमता 750 से 900 किलो तक होती है। ट्रैक्टर संचालित कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन का रखरखाव भी बहुत कम और आसान होता है। यह एक ऐसी मशीन है जो खेतों, खुले मैदान से लेकर ग्रीन हाउस आदि में खाद फैलाने के काम आती है।

मशीन की कीमत और सब्सिडी

अगर कीमत की बात करें तो टैंकर वाले कम्पोस्ट स्प्रेडर की कीमत लगभग 45 से 50 हजार रुपए है। लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन पर की खरीद पर किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सामान्य किसानों को इस मशीन पर 50 प्रतिशत या अधिकमत 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि यह सब्सिडी 40 एचपी से ऊपर की कम्पोस्ट स्प्रेडर मशीन पर दी जाएगी।

प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा

किसानों को बोनस भुगतान के लिये 1000 करोड़ का बजट

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि विभाग को गत वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक बजट मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गए बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

लाड़ली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर- मंत्री राजपूत ने बताया है कि लाड़ली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 520 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

समिति विक्रेताओं के मानदेय में वृद्धि

मंत्री ने बताया है कि पैक्स एवं लैम्प्स समिति के विक्रेताओं के मानदेय में 3 हजार की वृद्धि की जा रही है। इससे 13 हजार से अधिक विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। इसके लिये बजट में 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करेंगे

बजट में नवीन योजना के रूप में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना मेंसार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सर्वर को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बजट में 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्हें गेहूं पर 4 रुपए किलो तथा चावल पर साढ़े पांच रुपए प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी।

हर परिवार तक पहुंचेगा राशन

प्रदेश में 1 करोड़ 23 लाख पात्र परिवारों को हर माह 1 रुपए प्रति किलो में आयोडीन/आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा 33 जिलों के 57 लाख पात्र परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो में डबल फोर्टीफाइड युक्त नमक का वितरण की योजना पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से हम 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखंडों में 7 लाख 13 हजार परिवारों को मोबाइल वाहन द्वारा राशन का वितरण कर सकेंगे।

राज्यपाल ने की वनविभाग की गतिविधियों की समीक्षा

यह भी कहा-वन मित्र पोर्टल को आवेदक रखें फेंडली

वनाधिकार पट्टा धारकों को मिले पीएम आवास का लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार पट्टा धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिले। पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अनिवार्यतः लाभ दिया जाए। पटेल ने उक्त निर्देश वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राजभवन में आयोजित बैठक में वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर और अपर मुख्य सचिव वन विभाग अशोक कुमार बर्णवाल मौजूद थे। राज्यपाल ने बैठक में वन मित्र पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल को आवेदक फ्रेंडली और पात्र हितग्राहियों की सहूलियत का विशेष ध्यान रख जाए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा धारकों के लिए खेल मैदान, हाट बाजार, मड़ई-मेले और श्मशान घाट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनजातीय समुदाय को लाभ दें- राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय को पीएम जनमन योजना के विभिन्न घटकों को संयोजित कर प्राथमिकता से लाभान्वित करें। उन्होंने बैठक में पीव्हीटीजी वनधन केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की। राज्यपाल वन अपराध में जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण कर त्वरित निराकरण के लिए मानिटरिंग की जाए।

विस्तार से समीक्षा कर निर्देश

राज्यपाल ने बैठक में लघु वनोपज संग्रहण अधिकार, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, नवीन ग्राम सभाओं के गठन के पश्चात उनके नजरी नक्शे और सीमांकन की स्थिति, तेंदू-पत्ता संग्रहण, गौण वनोपज का संग्रहण एवं प्रबंधन तथा विपणन, वनोपज की खरीदी एवं बिक्री, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के गठन, गौण वनोपज के प्रबंधन के लिए सूक्ष्म प्रबंध योजना, खनिज स्वामित्व को लेकर ग्राम सभाओ की स्थिति, आदि के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए।

सभी वर्गों का रखें ध्यान

वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि लघु वनोपज संग्रहण की नीतियों में जनजातीय वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण और गौण वनोपज के संग्रहण, प्रबंधन और विपणन में पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों को और अधिक विस्तारित किया जाए। पेसा प्रावधानों के आधार पर वनोपज संग्रहण, प्रबंधन और विपणन को और अधिक हितग्राही मूलक बनाने के संबंध में चिंतन भी किया जाए।

-प्रधानमंत्री जन-मन आवास का मिला लाभ

पक्का हो घर अपना... अब नहीं रहा ये सपना

भोपाल। जागत गांव हमार

खुद के पक्के घर में निश्चिंत होकर कौन नहीं रहना चाहता। यह सभी का एक बड़ा सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिये हर व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है। खुजरो बाई भी पक्के घर का सपना दिल में लिए जी रहीं थीं। मंडला जिले की ग्राम पंचायत जंतीपुर की खुजरो बाई बैगा की किस्मत रंग लाई और अब उसे प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना से खुद का पक्का घर मिल गया है। पक्का घर पाकर वे बेहद प्रसन्न हैं। इस योजना ने पक्के घर में रहने का उनका बरसों पुराना सपना साकार कर दिया है। खुजरो बाई बताती है कि वे बेहद गरीब परिवार से हैं और सालों से कच्चे मकान में रहती थीं। कच्चे मकान में रहने पर बारिश में उसे बड़ी परेशानी होती थी। बारिश की वजह से उसका घर-गृहस्थी का सामान भीगकर खराब हो जाता था। हर साल बारिश से पहले घर की मरम्मत में बहुत पैसा खर्च हो जाता था। वह मजदूरी करके अपना भरण-पोषण करती थीं। गरीबी के कारण वह अपना पक्का मकान नही बना पा रही थी। इसी दौर में ग्राम पंचायत जंतीपुर द्वारा उसे बताया गया कि 2023-24 में उसका नाम प्रधानमंत्री जन-मन योजना की आवास चयन सूची में आ गया है। योजना के तहत उसे तीन किश्तों में काम के आधार पर धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में दी गई और उसे कुशल मजदूरी का भुगतान भी किया गया।

खुजरो बाई के अब अच्छे दिन

खुजरो बाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-मन योजना से उसका पक्का घर बन गया है और अब वह इसमें रहने भी लगी हैं। वे यह भी बताती है कि उन्हें सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, विद्युत कनेक्शन, पक्का शौचालय, नल कनेक्शन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का लाभ भी मिल रहा है। सरकार की इन सभी योजनाओं का लाभ पाकर खुजरो बाई के दिन अब बदल गए हैं। वे प्रधानमंत्री जन-मन योजना से उसे पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार जताती हैं।

निर्णयों की प्रतीक्षा में देश की आधी आबादी का पूरा अधिकार

महिलाओं को भूमि अधिकार सुनिश्चित करना और किसान के रूप में वैधानिक मान्यता देना- समाज और सरकार के समक्ष सदियों से लंबित है। ऐसा हो सकने और न हो सकने के मध्य, इस देश की आधी आबादी अर्थात महिलाएं, अपने तमाम अधिकारों के प्रति (अ)सामाजिक अस्वीकृति की आखेट हैं, जिसे औसत रूप से सामाजिक - संहिता (और कुछ हद तक सामाजिक मान्यता) मान लिया गया। महिलाओं को अधिकार देने का अर्थ और परिणाम, पुरुषप्रधान समाज को कमजोर कर देना होगा, यह असुरक्षा की भावना और संभावना-सामाजिक और राजनैतिक जड़ता के रूप में लगभग स्थायी हो चुकी है।

'संपत्ति के अधिकार' के कानून अथवा 'महिला कृषकों' के लिए सरकारी योजनाओं का पिटारा-कोई भी समाज और सरकार की सोच और सफलता को प्रभावित, लगभग नहीं ही कर पाया है। विडंबना ही है कि स्वाधीनता के स्वर्णकाल में महिलाओं के भूमि अधिकार तय करना या न करना - एक अदद सवाल तक नहीं बन पा रहा है।

भारत में स्वाधीनता के बाद से ही महिलाओं के भूमि अधिकार अथवा महिला किसानों के अधिकार - निर्णायक विषय न बन पाने के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण पक्ष 'महिलाओं के कमतर राजनैतिक प्रतिनिधित्व और प्रभुत्व' से समझा जा सकता है। स्वाधीन भारत के प्रथम संसदीय चुनाव (1952) में निर्वाचित महिला सांसदों का संख्याबल 24 (4 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 74 सांसदों (14 प्रतिशत) तक तो पहुंचा, लेकिन यह महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करनें वाले आवश्यक-संख्यात्मक संसदीय जनादेश के लिये पर्याप्त नहीं है।

ज़ाहिर है, संसद में निर्वाचित महिला सांसदों का यह कमतर अनुपात, महिला अधिकार केंद्रित विषयों पर संसदीय निर्णयों अथवा कानूनों की स्थापना के लिए अपर्याप्त है। वर्ष 2011 में डॉ स्वामीनाथन द्वारा संसद में आधी आबादी के अधिकारों के लिए प्रस्तुत 'महिला कृषक हकदारी क़ानून' के प्रस्ताव पर पर्याप्त राजनैतिक चर्चा और निर्णय न हो पाना-बहुसंख्यक पुरुष प्रधान संसदीय मानसिकता का जगजाहिर उदाहरण है।

सवाल है कि-क्या पुरुषप्रधान संसद, कभी महिलाओं के भूमि अधिकारों और महिला किसानों के अधिकारों के क़ानून पारित करेगा? विगत 75 बरसों के संसदीय इतिहास का सरल उत्तर तो 'नहीं' है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि राजनैतिक दलों में महिलाओं का (अनुपातिक रूप से) आधा प्रतिनिधित्व न हो जानें तक अर्थात निर्णायक संसदीय भागीदारी न होनें तक, महिलाओं के अधिकारों के प्रयासों को निर्णायक नहीं माना जा सकता ?

महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने और होते हुए दिखाई देने के मध्य, वास्तव में वह पुरुषकेंद्रित व्यवस्था है जो अब तक-महिलाओं के भूमि अधिकारों और महिला किसानों के सवालों को समाज की ओर धकेलता रहा है।

सवाल यह भी है कि, क्या आधी आबादी का आधा (संख्यात्मक) प्रतिनिधित्व महिलाओं के भूमि और किसानी के अधिकारों के पारित होने की पहली संसदीय शर्त है? संसद के लिये निर्वाचित महिलाओं के प्रतिनिधित्व का शोचनीय अनुपात यह कहता है कि, 'हाँ' जब तक महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व संख्याबल की दृष्टि से आधा नहीं हो जाता, तब तक महिला भूमि अधिकारों और महिला किसानों के अधिकारों से जुड़े वैधानिक प्रस्तावों की राजनैतिक अवमानना जारी रहेगी। पुरुषप्रधान राजनैतिक दल इस सत्य को भी खारिज ही करेंगे।

वर्ष 2024 के संसदीय चुनावों के बाद महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 14 प्रतिशत ही है - इसीलिये उनके दायित्व और प्रतिनिधित्व का भार, निर्वाचित पुरुष सांसदों से कहीं अधिक हैं। भारत की मौजूदा जनसँख्या के अनुसार, लोकसभा में एक निर्वाचित सांसद औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं एक निर्वाचित महिला सांसद (आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से)

औसतन 92 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करतीं हैं।

ऐसे में निर्वाचित महिला सांसदों का राजनैतिक दायित्व भी कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह भी है कि 14 प्रतिशत संख्याबल के साथ, उनका महिला भूमि अधिकारों और महिला किसानों के अधिकारों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण, लेकिन महिला अधिकारों की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा।

आज छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जहां महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व पूरे देश में अव्वल अर्थात 18 प्रतिशत है। आश्चर्य है, विधानसभाओं में महिलाओं का आनुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व , प्रगतिशील और राजनैतिक साक्षरता के प्रतिनिधि राज्यों - जैसे केरल में 9 प्रतिशत, तमिलनाडु में 5 प्रतिशत, गुजरात में 8 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत और कर्नाटक में 4 प्रतिशत, अर्थात शोचनीय है।

जबकि तथाकथित पिछड़े घोषित राज्यों, जैसे, बिहार में 12 प्रतिशत, राजस्थान में 14 प्रतिशत, झारखण्ड में 12 प्रतिशत, ओडिशा में 12 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 14 प्रतिशत, अर्थात अपेक्षाकृत उत्साहवर्धक है। महिलाओं के भूमि अधिकारों को लेकर लगभग स्थायी हो चुके राजनैतिक जड़ता के लिये महिला विधायकों का यह सीमित प्रतिनिधित्व, महिलाओं के भूमि और किसानी के अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थापित करने मे एक कठिन नैतिक-राजनैतिक चुनौती है।

जाहिर है महिला अधिकारों और महिलाओं के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के राजनैतिक दावों और उसकी वास्तविकता के मध्य एक गहरा राजनैतिक विरोधाभास और राजनैतिक दलों का दोगलापन है। समाज (और विशेष रूप से महिलाओं) के द्वारा इसे हासिल न कर पानें की क़ीमत, 'महिलाओं के अधिकारों' की अवमानना के रूप में, दशकों से हम सब चुका रहे हैं।

संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित महिलाओं के प्रतिनिधित्व से - महिलाओं के भूमि अधिकार और महिला किसानों की मान्यता के सदियों पुरानें सवाल समाप्त होंगे, यह मान लेने के पर्याप्त कारणों में सर्वप्रमुख है-बहुसंख्यक महिलाओं की चाहत कि उनकी अपनी भी ज़मीन हों ताकि वो अपनी जड़ें परिवार, समाज और देश में मज़बूत कर सकें।

छत्तीसगढ़ के पामगढ़ विधानसभा से प्रथम बार निर्वाचित विधायक शेषराज हरबंस कहतीं हैं कि, महिलाओं के अधिकारों का सवाल अब तो सपनें से यथार्थ में बदलना ही चाहिये, इसीलिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के माध्यम से मेरा प्रयास महिलाओं के भूमि अधिकारों के राजनैतिक सवाल का ज़वाब देना होगा। महिला विधायकों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अग्रगामी छत्तीसगढ़, यदि महिला भूमि अधिकार और महिला किसानों के हक़ को वैधानिक मान्यता देने का क़ानून पारित कर पायी, तो पूरे देश के लिये निश्चित ही यह मिसाल बनेगी।

आज पूरी दुनिया जब महिलाओं के अधिकारों को सुलझानें - उलझाने के प्रयासों में व्यस्त है, तब महिला सशक्तता की प्रथम शर्त 'महिलाओं के बढ़ते राजनैतिक प्रतिनिधित्व' के बरकस, समाधानों की ओर पहला क़दम हो सकती है।

ऐसा हो पाने का अर्थ, संविधान में दर्ज आधी आबादी को उसका अधिकार सुनिश्चित करना होगा, जो भारत के 60 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिये इक्कीसवीं सदी का सबसे सबल 'राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक' अधिकार और आधार स्थापित करेगा। निश्चित रूप से इन प्रयासों के केंद्र में राजनैतिक दल और उनसे जुड़े महिला समाज का राजनैतिक अस्तित्व निर्भर है। आज, अपनें राजनैतिक अस्तित्व और अधिकार की उम्मीदों के साथ भारत देश की आधी आबादी - हमारे आपके निर्णयों की प्रतीक्षा में है।

लेखक रमेश शर्मा, एकता परिषद के महासचिव हैं।

पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार देता फूलों का कचरा

जैसे-जैसे भारत स्थिरता और सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, कचरे से संपदा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना ही रास्ता है। मंदिरों में खाद बनाने के गड्ढे बनाने और पुनर्चक्रण प्रयासों में मंदिर ट्रस्टों तथा स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा हो सकते हैं। पुजारियों और भक्तों को नदियों में फूलों का कचरा न डालने को लेकर उन्हें शिक्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम से कचरे में कमी लाने में मदद मिल सकती है। हरित मंदिर अवधारणा को मंदिरों को पर्यावरण के अनुकूल स्थानों में बदलने की नीतियों में एकीकृत किया जा सकता है। स्वाभाविक तरीके से सड़नशील सामग्रियों को बढ़ावा देने से भी फूलों के कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

भारत में फूलों के अपशिष्ट का क्षेत्र नई वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जिसका इसके बहुआयामी लाभों से पता चलता है। यह न केवल महिलाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि कचरे को कूड़ा-स्थलों से प्रभावी ढंग से हटाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है।

आध्यात्मिक स्थलों से एकत्र किया गया फूलों का अपशिष्ट, जो कि ज्यादातर स्वाभाविक तरीके से सड़नशील होता है, अक्सर लैंडफिल या जल निकायों में समाप्त हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवतज्ञ रिपोर्ट के अनुसार, अकेले गंगा नदी सालाना 8 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक फूलों के कचरे को सोख लेती है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, कई भारतीय शहर अभिनव समाधान ला रहे हैं। सामाजिक उद्यमी फूलों से जैविक खाद, साबुन, मोमबत्तियां और अगरबत्ती जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

महाकालेश्वर मंदिर: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज 75,000 से 100,000 तक दर्शनार्थी आते हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5-6 टन फूल और अन्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके लिए खास 'पुष्पांजलि इकोनिर्मित' वाहन हैं, जो इस कचरे को एकत्र करते हैं और फिर इसे थ्रीटीपीडी प्लांट में संसाधित करके पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदल दिया जाता है। शिव अर्पण स्व-सहायता समूह की 16 महिलाएं फूलों के कचरे से विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाती हैं और इसके लिए उन्हें रोजगार भी दिया गया है। इसके अलावा, इस कचरे से स्थानीय किसानों के लिए खाद बनाया जाता है और यह जैव ईंधन के रूप में भी काम करता है। उज्जैन स्मार्ट सिटी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 2,200 टन फूलों के कचरे से कुल 3,02,50,000 स्टिक का उत्पादन किया गया है।

सिद्धि विनायक मंदिर: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना करीब 40,000-50,000 श्रद्धालु आते हैं। कुछ खास दिनों में तो यह आंकड़ा 1,00,000 तक पहुंच जाता है, जो 120 से 200 किलोग्राम फूल चढ़ाते हैं। मुंबई स्थित डिजाइनर हाउस 'आदिव प्योर नेचर' ने एक स्थायी उद्यम शुरू किया है, जो मंदिर में अर्पित किये गए फूलों को प्राकृतिक रंगों में बदलकर कपड़े के टुकड़े, परिधान, स्कार्फटेबल लिनेन और बड़े थैले के रूप में अलग-अलग वस्त्र बनाता है। वे सप्ताह में तीन बार फूलों का अपशिष्ट इकट्ठा करते हैं, जो 1000-1500 किग्रा/सप्ताह होता है। इस कचरे की छंटाई के बाद कारीगरों की एक टीम सूखे फूलों को प्राकृतिक रंगों में बदल देती है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदा, गुलाब और अड़हुल के अलावा, टीम प्राकृतिक रंग बनाने और भाप के माध्यम से बनावट वाले प्रिंट बनाने के लिए नारियल के छिलकों का भी उपयोग करती है।

तिरुपति बालाजी: तिरुपति नगर निगम हर दिन मंदिरों से 6 टन से जूयादा फूलों का अपशिष्ट उठाता है। वहां फूलों के कचरे को इकट्ठा करके उसे दोबारा इस्तेमाल करने योग्य मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। इसके ज़रिए स्वयं सहायता समूहों की 150 महिलाओं को रोजगार मिला है। रीसाइकिलिंग का यह काम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अगरबत्ती के 15 टन क्षमता वाले निर्माण संयंत्र में किया जाता है। इन उत्पादों को रीसाइकिल किए गए कागज और तुलसी के बीजों से भरे कागज से पैक किया जाता है ताकि कार्बन उत्सर्जन शून्य हो।

फूलों के कचरे की रीसाइकिलिंग करने वाले कानपुर स्थित 'फूल', प्रतिदिन विभिन्न शहरों के मंदिरों से फूलों का अपशिष्ट एकत्र करके बड़े-बड़े मंदिरों को इस कचरे की समस्या से निजात दिला रहा है। यह 'फूल' भारत के पांच प्रमुख मंदिर शहरों अयोध्या, वाराणसी, बोधगया, कानपुर और बद्रीनाथ से लगभग 21 मीट्रिक टन फूलों का अपशिष्ट प्रति सप्ताह (3 टीपीडी) एकत्र करता है। इस कचरे से अगरबत्ती, धूपबत्ती, बांस रहित धूपबत्ती, हवन कप आदि जैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं। 'फूल' द्वारा नियोजित महिलाओं को सुरक्षित कायज स्थान, निश्चित वेतन, भविष्य निधि, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभ मिलते हैं। गहन तकनीकी शोध के साथ, स्टार्टअप ने 'फ्लेदर' विकसित किया है, जो पशु चमड़े का एक व्यवहार्य विकल्प है और इसे हाल ही में पेटा (पीईटीए) के सर्वश्रेष्ठ नवाचार शाकाहारी दुनिया से सम्मानित किया गया था।

विदेशी कीड़े बने दोस्त, आक्रामक जलीय खरपतवार को किया खत्म

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तवा नदी पर बने 2,800 एकड़ के सारणी जलाशय में छोड़े गए एक विदेशी कीड़े की मदद से जलाशय में फैल चुकी खतरनाक जलीय खरपतवार सालवीनिया मोलेस्टा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। स्थानीय भाषा में चाइनीज झालर के रूप में बदनाम में यह आक्रामक प्रजाति सबसे पहले 2018 में देखी गई और 2019 तक इसने पूरे जलाशय को घेर लिया था। यह जलाशय बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अधीन है और जलाशय के किनारे उसका सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है। कंपनी के चीफइंजीनियर वीके कैथवार के अनुसार सालवीनिया मोलेस्टा का हटना हमारे लिए विज्ञान का चमत्कार है।

जबलपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के निदेशक जेएस मिश्र ने बताया कि पहले एनटीपीसी ने हाथ से आक्रामक प्रजाति को हटाने की रणनीति बनाई थी और इस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। यह उपाय कारगर नहीं था क्योंकि इसमें खरपतवार के फिर से आने की आशंका है। मिश्र बताते हैं कि जब कंपनी को पता चला कि एक विदेशी कीट (सिटोर्बेगस सालवीनिया) की मदद से खरपतवार को हटाया जा सकता है तो उन्होंने निदेशालय से संपर्क किया और फिर अप्रैल 2022 से जलाशय में कीट छोड़ने का सिलसिला चला। 15 से 18 महीने में कीट ने अपनी आबादी कई गुणा बढ़ाकर खरपतवार को नष्ट कर दिया।

आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर के वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्राजील मूल के सालवीनिया मोलेस्टा को खाने वाले बायो एजेंट सिटोर्बेगस सालवीनिया पर गहन शोध के बाद ही इसे भारत लाया गया और सरकार की अनुमति के बाद इसे खरपतवार पर छोड़ा गया है।

सालवीनिया मोलेस्टा को खाने वाला बायो एजेंट सिटोर्बेगस सालवीनिया खतपतवार के साथ ही खुद भी खत्म हो जाता है

सारणी जलाशय वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा और सफल प्रयोग है। निदेशालय सारणी जलाशय में कीट को छोड़ते वक्त पूरी तरह आश्वस्त था कि इससे जलीय खरपतवार को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसने इसकी सफलता का पहला प्रयोग कटनी जिले के पडुआ गांव के एक तालाब पर कर लिया था। करीब 20 हे. में फैले इस तालाब से 18 महीने में कीट ने आक्रामक प्रजाति सालवीनिया मोलेस्टा को नष्ट कर दिया था।

आईसीएआर-डीडब्ल्यूआर के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक और मध्य भारत में कीट का प्रयोग करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार कहते हैं कि प्रति हे. 22,500 कीटों को छोड़ने पर अच्छे नतीजे मिलते हैं। 15 महीने में कीट खरपतवार को खा जाते हैं।

सरकारी भंडार में जरूरत से ज्यादा है अनाज का स्टॉक

केंद्र स्कीम के तहत राज्यों को बेचा जा सकेगा चावल

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार के सरकारी भंडार में जरूरत से ज्यादा चावल का स्टॉक है। ऐसे में वह अतिरिक्त चावल बेचने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि वह ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राज्यों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से चावल खरीदने की अनुमति दे सकती है। तीन जुलाई, 2024 तक केंद्रीय पूल में उपलब्ध चावल का स्टॉक 329.17 लाख मीट्रिक टन था। यह बिना पिसाई वाले धान के स्टॉक से अलग है, जिससे एफसीआई को 153.07 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल मिलेगा। इसके बाद कुल चावल का स्टॉक 482.24 लाख टन तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 400 लाख टन की सलाना जरूरत से अधिक है। नई खरीफ फसल आने में बस 3-4 महीने बाकी हैं। इसलिए चावल के स्टॉक में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बफर मानदंडों के अनुसार, केंद्र को जुलाई के पहले दिन 135.40 लाख मीट्रिक टन चावल का स्टॉक बनाए रखना जरूरी है। केंद्र को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चावल के अतिरिक्त स्टॉक को बनाए रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की वहन लागत उठानी पड़ी और चालू वित्तीय वर्ष में इसमें 1,600 करोड़ रुपये और बढ़ने की उम्मीद है।

केवल 1.72 लाख टन चावल बेचा

सूत्रों ने कहा कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से अतिरिक्त स्टॉक को खाली करने के प्रयासों से उचित परिणाम नहीं मिले हैं। केंद्र द्वारा 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल की पेशकश करने के बावजूद 39.31 रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक लागत से काफी कम - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई-नीलामी के माध्यम से केवल 1.72 लाख टन चावल बेचा गया।

कर्नाटक को 2.28 लाख टन चावल की जरूरत

पिछले साल जून में, केंद्र ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के दायरे से बाहर कर दिया था, जिससे उन्हें एफसीआई से चावल खरीदने से रोक दिया गया था। इस कदम से कर्नाटक जैसे राज्य प्रभावित हुए, जिन्होंने अन्न भाग्य योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए एफसीआई से 2.28 लाख मीट्रिक टन मांगा था।

चावल की कीमत कम कर सकती है सरकार

एक सूत्र ने बताया कि मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल के मौजूदा 29 रुपये के आरक्षित मूल्य को कम किया जाए या नहीं। एक सूत्र ने बताया कि कीमत में 1-2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह इथेनॉल के लिए डिस्टिलरी को चावल की आपूर्ति फिर से शुरू करने के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। सूत्र ने बताया कि इन विकल्पों पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह को विचार करना है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

किसानों को मिलती है हजारों रुपये की सब्सिडी

किसानों के लिए फायदेमंद, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तीन योजनाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत को हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता रहा है। आज जहां दुनिया बदल रही है तो खेती के तरीके भी मॉर्डन और टेक्निकल होने लगे हैं। लेकिन इन तरीकों के बीच ही अब भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा है। देश में कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिनके तहत प्राकृतिक खेती करने पर किसानों को प्रोत्साहन के तौर सब्सिडी दी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है प्राकृतिक खेती और इसे बढ़ावा देने के लिए चलाई गईं कुछ खास योजनाओं के बारे में।

प्राकृतिक खेती और योजनाएं : प्राकृतिक खेती यानी खेती करने का वह तरीका जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है और जिसमें सिर्फ प्राकृतिक तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है। इस खेती में इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर फसलों, पेड़ों और जानवरों के बीच तालमेल को बढ़ाया जाता है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि मिट्टी के पोषक तत्व बरकरार रहें।

परंपरागत कृषि विकास योजना- वर्ष 2015-16 में, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। इसके तहत 31,000 रुपये की राशि को प्रति हेक्टेयर 3 सालों जैविक पदार्थों जैसे कि जैविक उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों की खरीद के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मूल्यवर्धन और वितरण के लिए 8,800 रुपये की राशि प्रति हेक्टेयर तीन सालों के लिए दी जाती है।

नमामि गंगे प्राकृतिक खेती कार्यक्रम

इस योजना के तहत 1,23,620 हैक्टर भूमि और प्राकृतिक खेती की 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाता है। इस तरह से कुल 32,384 क्लस्टर बनाये गये हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में किसान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस योजना के जरिये से एक स्थायी प्राकृतिक कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति

साल 2019 में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उपयोजना-भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के जरिये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसका मकसद पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह किसानों को बाहरी रूप से खरीदे गए संसाधन से आजादी देता है। इसके तहत तीन सालों के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

अलीराजपुर की प्राचीन बावड़ी को मिल गया नया जीवन

भोपाल। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में प्राचीन बावड़ी एवं जल-संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अलीराजपुर जिले में जोबट स्थित देव स्थान पर बनी प्राचीन बावड़ी का सफाई और जीर्णोद्धार किया गया। बावड़ी में लम्बे समय से गाद, मिट्टी और कचरा निकालने का कार्य जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से किया गया। प्राचीन बावड़ी में लगे पीपल के पौधों को सुरक्षित निकाल कर अन्य स्थान पर रोपण किया गया। करीब 60 फीट गहरी बावड़ी वर्ष 1906 की है। प्राप्त शिलालेख के अनुसार बावड़ी का निर्माण तत्कालीन नगर कोतवाल ने कराया था। बावड़ी के सफाई कार्य में 10 ट्रॉली गाद और कचरा निकाला गया है। बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया है। सुरक्षा के लिए मुंडेर बनाई गई है। इसके साथ ही हैंडपंप भी लगाया गया है। हैंडपंप से अब मंदिर परिसर में भक्तों को साफ पानी मिल रहा है। बावड़ी की सीढ़ियों पर जाली लगाकर उसे और सुरक्षित किया गया है। इंदौर संभाग में कमिश्नर दीपक सिंह के

मार्गदर्शन में संभाग के सभी जिलों में प्राचीन बावड़ी और जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। अलीराजपुर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि अलीराजपुर में अनेक प्राचीन बावड़ियां हैं, इन्हें चिन्हित कर इनके जीर्णोद्धार के लिये कार्य-योजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने इंदौर के अटल वन में किया पौध-रोपण

चुनौतियों का समाधान कारक होगा पौध-रोपण का महाअभियान

भोपाल। जागत गांव हमार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में इंदौर में चल रहे 51 लाख पौधे लगाने के महा अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इंदौर के बिजासन के समीप अटल वन में पौध-रोपण भी किया। बिरला ने पौध-रोपण अभियान को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है ऐसे में यह अभियान पर्यावरण अनुकूलता की दिशा में देश और दुनिया को नया दृष्टिकोण देते हुए नई राह दिखाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मध्यप्रदेश विशेषकर इंदौर में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह अभियान जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। पौध-रोपण हमारी संस्कृति, संस्कार एवं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यह अभियान वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुखद बनाने का अभियान है। देश एवं विश्व की पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान का माध्यम भी बनेगा।

मानव जीवन को बचाने का अभियान

वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह अभियान मानव जीवन को बचाने का वृहद अभियान है। यह एक अच्छा कार्य है। इस अभियान को निरन्तर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृगांर है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। वृक्ष से ही जीवन की निर्भरता है। वृक्ष हमें जीवन बचाने के लिए सब कुछ देता है। हमारा फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाये और उनकी सुरक्षा का संकल्प लें।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारः 15 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

गाय, भैंस पालन करने वाले को दिया जाएगा 5 लाख रुपये तक का पुरस्कार

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों की स्थायी आजीविका के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लें सशक्त हैं और उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता भी है। वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, 2021 से यह विभाग दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों/एमपीसी/एफ्मीओ और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एआईटी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के लिए है-

स्वदेशी गाय/भैंस नस्ल का पालन करने वाला सवज्श्रेष्ठ डेयरी किसान (पंजीकृत नस्लों की सूची संलग्न)। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस)/दूध उत्पादक कंपनी (एमपीसी)/डेयरी

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)। इस वर्ष से, विभाग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एनजीआरए 2024 प्रत्येक श्रेणी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एनजीआरए 2024 में पहली दो श्रेणियों यानी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डीसीएस/एफ्मीओ/एमपीसी में योग्यता प्रमाणपत्र, एक स्मृति चिन्ह और मौद्रिक पुरस्कार शामिल होंगे।

5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) -प्रथम रैंक
3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) -दूसरी रैंक और
2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) -तीसरी रैंक
2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) -उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए विशेष पुरस्कार।

एआईटी श्रेणी में कोई नकद पुरस्कार प्रदान नहीं

सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी के मामले में, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार-2024 में केवल योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होगा। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी में कोई नकद पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। 2024 के पुरस्कारों के दौरान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन 15.07.2024 से शुरू होकर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यानी https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2024 होगी। पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर, 2024) के अवसर पर प्रदान किए जाने हैं। पात्रता और ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित दिशानिदेशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://awards.gov.in या https://dahd.nic.in देखी जा सकती है।

तिलहन प्रदर्शन 2024-25 के अंतर्गत सोयाबीन बीज वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत इकाई कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में तिलहन प्रदर्शन सोयाबीन का 80 हेक्टेयर में 200 प्रदर्शन जिलें के विभिन्न ग्रामों में किए गए। क्लस्टर प्रभारी डॉ. निधि वर्मा, वैज्ञानिक शस्य विज्ञान द्वारा ग्राम खुलरी, मानेगांव, हिरनपुर, चीला चोन कला एवं करताज में कृषकों के लिए इस संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26.06.2024 विकासखण्ड करेली में किया गया। जिसमें कृषको को सोयाबीन की उन्नत किस्में जे.एस. 20-98 एवं जे.एस. 21-72 किस्म की जानकारी प्रदान की।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है यह किस्म 10 वर्ष के अंदर की है। यह 95 से 110 दिन में पक कर तैयार होती है। इसकी उपज 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है साथ ही यह किस्म रोग एवं कीट आदि के प्रतिरोधक क्षमता है। जिले में सोयाबीन का रकबा पीला मोजेक विषाणु के प्रकोप से दिनों दिन घटता जा रहा है। इससे

फसल को 80 प्रतिशत तक हानि होती है इस केस में देखा गया कि पीला मोजेक एवं चारकोल रॉट के प्रति प्रतिरोधी है। वैज्ञानिकों द्वारा बीज उपाचार के फफूंदनाशक कार्बोक्सिन 37.5 प्रतिशत . थायरम 37.5 प्रतिषत डीएस 3 ग्राम दवा या थाओफेनेटमिथाइल 45 प्रतिशत. पायराक्लोरस्टोबिन 5 प्रतिशत एफएस दवा 1-1.25 मिली/किग्रा बीज दर से या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम नामक जैविक फफूंदनाशक के 5 ग्राम / बीज की दर सें उपचारित कर सकतें है। इससे बीज एवं मृदाजनित रोगों पर नियत्रंण पाया जा सकता है। कार्यक्रम में ग्राम खुलरी के 50 कृषकों एवं करेली विकासखण्ड से 100 कृषकों प्रषिक्षण एवं बीज उपलब्ध कराया गया। नरसिंह इको फुडस् प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड के प्रभारी योगेन्द्र तथा शक्ति पूजा महिला किसान प्रोड्यूसर कपंनी लिमि. करेली के प्रभारी जगदीश मेहरा के समन्वय से कृषकों को सोयाबीन का बीज वितरण कराया गया।

खरीफ की फसलों के विपुल उत्पादन हेतु वैज्ञानिकों की तकनीकी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक . डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के समय उन्नत तकनीक अपनाने की सलाह दी गयी। किसान उड़द की पीला मौजेक प्रतिरोधक किस्में -इंदिरा उड़द प्रथम, मुकुंदरा.2, प्रताप उड़द 1, प्रताप उड़द 9, आईपीयू 13.1, कोटा उड़द.2, कोटा उड़द.3, कोटा उड़द.4, सोयाबीन की उन्नत किस्में -जेएस 20.116, जेएस 20.34, जेएस् 20.94, जेएस् 20.98, जेएस 22.12, एनआरसी् 150, मूँगफल्ली की उन्नत किस्में-जीजेजी.32, टीसीजीएस 1694, लेपाक्षी, जेएल 501, जेजीएन 313.1, तिल की उन्नत किस्में-टीकेजी 306, टीकेजी 308, जीटी् 4, जीटी 6, आदि उन्नत किस्मों की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय बीज निगम निवाड़ी एवं मप्र राज्य बीज निगम, कुण्डेश्वर रोड, टीकमगढ़ सम्पर्क कर बीज प्राप्त किया जा सकता है।

बीजोपचार कर बुवाई करना चाहिए

फसल को फफूंद जनित बीमारियों से बचाने के लिए जैविक फफूंदनाशक दवा ट्राईकोडर्मा विरिडी 10 मिली या रासायनिक दवा विटावैक्स पॉवर 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से बीजोपचार कर बुवाई करना चाहिए। खरीफ फसलों के अधिक उत्पादन के लिए फसलों की बुवाई कतारों में करना चाहिए और फसलों में मिट्टी परीक्षण उपरान्त अनुसंशित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दलहनी और तिलहनी फसलों में फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए जिससे पफ्सलों को फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी प्राप्त हो जाता है। फसलों में कीट.व्याधियों से बचाव के लिए न्यूट्रेट ऑफपोटाश का 15.20 किग्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाईयों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रति वर्ष प्रत्येक खेत में फसलें अदल.बदल कर बोना चाहिएए जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी और कीट-व्याधियों की समस्या भी नहीं होगी।

छिंदवाड़ा का गांव झिरलिंगा, जहां हर किसान करता है ग्रीष्मकालीन देशी कद्दू की खेती

छिंदवाड़ा। जागत गांव हमार

उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह एवं सहायक संचालक कृषि धीरज ठाकुर ने बुधवार को ग्राम झिरलिंगा में ग्रीष्मकालीन देशी कद्दू की खेती का अवलोकन किया। जिले का यह एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ हर किसान ग्रीष्मकालीन कद्दू लगाता है। इस ग्राम के किसान नरेश ठाकुर, सरपंच, इन्द्रसेन ठाकुर, हरीश ठाकुर, रायसिंग ठाकुर, बृजकुमार ठाकुर, नेकराम साहू, लक्ष्मण ठाकुर, कैलाश ठाकुर, कुबेर ठाकुर के साथ ही इस ग्राम के शत-प्रतिशत किसानों के द्वारा कद्दू फसल की खेती की जा रही है।

उप संचालक कृषि सिंह ने बताया कि ग्राम के लगभग 400 किसानों द्वारा लगभग 500 एकड़ में कददू फ्सल लगाई गई थी। प्रति एकड़ 10 टन

उत्पादन के मान से कम से कम एक लाख रूपये प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ किसानों ने प्राप्त किया है। प्रति किलो 13-14 रूपये के मान से व्यापारी किसान के खेत से ही उठाकर ले जा रहे है। ग्रीष्मकालीन कद्दू की बोनी होली के बाद रामनवमी तक की जाती है। किसान बिना कीटनाशक दवा के देशी कद्दू के बीज स्वयं तैयार कर बोनी करते है, जिससे किसानों को लागत कम आती है एवं मुनाफ अधिक होता है। छिंदवाड़ा जिले के लगभग 20-25 ग्रामों मे 2000 एकड़ में कद्दू की खेती की जा रही है।

उप संचालक कृषि से चर्चा के दौरान किसानों द्वारा बताया गया कि अधिकतम कद्दू का वजन लगभग 65 किलोग्राम एवं औसतन 20-25 किलोग्राम होता है। जिले में कद्दू का टर्नओवर लगभग 20 करोड़ रूपये हैं। यह कद्दू प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेश बिहार, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि प्रदेश में जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि सिंह के साथ सहायक संचालक कृषि ठाकुर एवं ग्राम के किसान उपस्थित थे।

मूँगफली फसल उत्पादन की तकनीकी समसामयिक जानकारी

वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे करें मूंगफली की उन्नत खेती और लें अच्छा उत्पादन

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डा. बीएस किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिकों डा. एसके सिंह, डा. आरके प्रजापति, डा. यूएस धाकड़, डा. एसके जाटव, डा. आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा बताया गया कि मूँगफली की खेती भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की बलुई दोमट भूमि, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होए खेतों में की जा सकती है। खेत को दो-तीन बार जुताई करके 5 टन गोबर की खादए 60 किग्रा. फास्फोरस, 20 किग्रा. पोटाश, जिंक की कमी वाले खेत में 25 किग्रा. जिंक सल्फेट तथा गंधक की कमी वाले खेत में 20 किग्रा. गंधक अंतिम जुताई करके पाटा चला कर खेत तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाई हमेशा बीज उपचार के पश्चात् ही बोनी करें। मूँगफली के बीज को विटावैक्स पावर कार्बोक्सिन 37.5: थिरम 37.5:द्ध 2 ग्राम प्रति किग्रा. की दर से उपचार करने के पश्चात् कतारों में बोनी करें। कतार में बोनी करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। फसल में 25.30 दिन के अंदर निंदाई.गुड़ाई का कार्य किया जाना आवश्यक होता है, जिससे जड़ों का फैलाव अच्छा हो सके साथ ही भूमि में वायु संचार भी बढ़ जाता है और निंदाई.गुड़ाई का कार्य करने से फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य स्वत: ही हो जाता है। यदि किसान भाई कतार में बोनी करते हैं तो निंदाई.गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, दवा का छिड़काव आदि कार्य सुगमता से हो जाते हैं और बीज की मात्रा भी छिटकवाँ विधि की अपेक्षाकृत कम लगती है। यदि किसान भाई कतार विधि से बोनी करते हैं तो 30.35 किग्रा. बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। मूँगफ्ली की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रजाति का चयन करना।

मूँगफली की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का चयन हम बोनी हेतु कर सकते हैं जैसे- लिपाक्षी कादरी, जीजेजी 32, टीजी 37ए, आईसीजीवी 350, आदि ये सभी प्रजातियाँ दस वर्ष के अंदर की विकसित हैं। यदि किसान भाइयों को निंदाई.गुड़ाई के कार्य में श्रमिक की समस्या होती है तो शाकनाशी दवा पर्ज खड़ी फसल में मात्रा 400 मिली. 150.200 ली. पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन के अंदर या खरपतवार की 2.4 पत्तियाँ निकलने पर हमेशा फ्लैट फैन अथवा फ्लड जेट नोजल से छिड़काव करना चाहिए।

कृषि विज्ञान केन्द्र सागर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक

सागर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर-1 एवं सागर-2 की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर के सभागार में डॉ. टीआर शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक, संचालनालय विस्तार सेवायें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की अध्यक्षता एवं डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, अटारी, जोन-9, जबलपुर की विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुई। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के विभाग प्रमुख के साथ ही दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों के उन्नत कृषकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के शुरूआत में केन्द्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. केएस यादव ने अतिथियों एवं सलाहकार समिति के सदस्यों का स्वागत किया, तत्पश्चात् केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसके तिवारी ने रबी 2023-24 की उपलब्धियां एवं आगामी खरीफ 2024 की कार्यज्योजना का प्रस्तुतिकरण दिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर-2 के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ0 आशीष त्रिपाठी ने सागर-2 कार्यक्षेत्र के विकासखण्डों के रबी 2023-24 की उपलब्धियां एवं आगामी खरीफ2024 की कायज्योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक अटारी ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगारोनमुखी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। निदेशक ने समीक्षा के दौरान दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए सलाह दिया कि केन्द्र पर एवं कृषकों के यहां कम लागत तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर-1 एवं सागर-2 से डॉ. ममता सिंह, डॉ.. वैशाली शर्मा, डीपी सिंह, मयंक मेहरा, सुखलाल वास्केल, योगेन्द्र सिंह बड़ेरिया आदि शामिल हुए।

घट सकता है सोयाबीन का रकबा

मक्का-दलहन फसल की खेती की तरफ किसानों का झुकाव

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इस साल सोयाबीन की खेती के रकबे और उत्पादन में कमी आ सकती है। क्योंकि जो प्रमुख सोयाबीन उत्पाद राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं इन राज्यों के किसान अब सोयाबीन की खेती को छोड़कर दाल और मक्के की खेती को अपना रहे हैं। उनका रुझान दाल और मक्के की खेती की तरफ बढ़ रहा है। बता दें की सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। मध्य भारत में मॉनसून के प्रसार के साथ ही प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में तिलहनी फ्सल सोयाबीन की बुवाई लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय सोयाबीन उत्पादक संघ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक ने कहा कि इस साल हम सोयाबीन के रकबे में गिरावट की उम्मीद कर रहे है।

उन्होंने कहा कि सोयाबीन के रकबे में गिरावट की प्रमुख वजह है कि किसान इसकी खेती से अब दूरी बना रहे हैं। अब किसानों का झुकाव मक्के और दलहनी फसलों की खेती की तरफ हो रहा है। क्योंकि पिछले साल किसानों ने मक्के की खेती में अच्छी कमाई की थी, जबकि दाल की कीमतें हमेशा ही अच्छी बनी रहती हैं। लेकिन सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा है। इसकी कीमत एमएसपी से भी नीचे चली जा रही है। इसलिए किसान भी यह सोच कर मक्के और दाल की खेती कर रहे हैं कि उन्हें इनकी खेती करने से सोयाबीन से अधिक कमाई होगी।

सर्वे कर रहा है SOPA

सोयाबीन की खेती के रकबे में गिरावट आने का जिक्र करते हुए डीएन पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश किसानों का झुकाव सोयाबीन छोड़ने के बाद मक्के की खेती की तरफ हो रहा है जबकि महाराष्ट्र के किसान सोयाबीन को छोड़कर अधिकतर दलहनी फसलों और कपास की खेती कर रहे हैं। देश में सोयाबीन की खेती के कुल रकबे की जानकारी को लेकर भारतीय सोयाबीन उत्पादक संघ एक सर्वे करा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सर्वे की रिपोर्ट अगले कुछ सप्ताह में सामने आ जाएगी उसके बाद स्पष्ट आंकड़ों का पता चल पाएगा।

बढ़ी है सोयाबीन की एमएसपी

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पांच जुलाई तक देश में 60.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बुवाई की जा चुकी थी। हालांकि साल 2023 में इस अवधि के दौरान 28.86 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गई थी। पिछले साल के खरीफसीजन के दौरान 124.11 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गई थी। इस दौरान सोयाबीन की कीमत मध्य प्रदेश के मंडियों में 3971 से लेकर 4,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सोयाबीन की एमएसपी तय की है। इस साल सोयाबीन पर 4892 रुपये की एमएसपी तय की गई है, जबकि पिछले साल यह 4600 रुपये प्रति क्विंटल थी। सोयाबीन की एमएसपी में इस साल 6.3 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है।

किसानों को प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों के बारे में दी गई जानकारी

मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने बीज मेला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

सतना। जागत गांव हमार

ग्राम सुधार समिति संस्था द्वारा प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पुराने पारंपरिक बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। संस्था द्वारा सतना जिले के मजगामा विकासखंड के 45 गांव पर आजिविका विकास कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यानिकीय विभाग, एवं वन विभाग, पंचायत विभाग के स्थानीय कर्मचारी , संस्था के समस्त सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण कृषक बंधु मौजूद रहे।

कृषि विस्तार अधिकारी अजय बागरी द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यानकी प्रबंधक मोहन सिंह मरावी, द्वारा विभागीय विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथ ही बागवानी से होने वाले लाभ एवं बागवानी करने के तरीके पर आधारित तकनीक एवं योजनाओं पर दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं वन विभाग के स्थानीय बीट गार्ड महेंद्र कुमार त्रिपाठी, द्वारा वन विभाग द्वारा संचालित योजना एवं वन उपज संकलन पर जानकारी दी गई तथा किसानो के साथ एक स्वास्थ्य संवाद स्थापित किया गया।

कार्यक्रम अधिकारी रविशंकर वर्मा द्वारा देसी खाद एवं प्राकृतिक की नियंत्रक बनाने रखरखाव करने इस्तेमाल करने के विषय पर जानकारी दी गई। वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता मंजू चैटर्जी द्वारा महिलाओं को आजिविका विकास पर विषय रखा गया। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों के अलावा क्षेत्र के कई किसान उपस्थित रहे।

किसानों को सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार,

बजट में बढ़ सकती है किसान सम्मान की राशि

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाए जाने समेत अतिरिक्त रियायतें देने का भी ऐलान कर सकती है। किसान स मान निधि से जुड़े धनराशि को भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है।

पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हितों में बड़े फैसले ले, जिससे नके बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती-किसानी को लेकर गंभीर है। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ समेत अन्य किसान संगठनों ने भी वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखा था। कृषि मंत्रालय ने भी अपनी तरफसे कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी का कहना है, हमने पहली मांग किसान स मान निधि को बढ़ाने की रखी है, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2018-19 में किसानों को छह हजार रुपये सालाना देने का प्रावधान रखा। उसके बाद से लगातार महंगाई बढ़ी है और किसानों की लागत भीद। इसको देखते हुए स मान निधि की राशि बढ़ाकर 10-12 हजार रुपये सालाना कर देना चाहिए।

केसीसी की लिमिट बढ़ने की उ मीद

वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर तीन लाख रुपये का ऋण लेने पर सालाना सात प्रतिशत का ब्याज लगता है, जिसमें से तीन प्रतिशत वापस किसान को मिल जाता है। यानी शुद्ध रूप से किसान को चार प्रतिशत की ब्याज पर केसीसी से ऋण मिलता है। महंगाई बढ़ने के साथ कृषि लागत में हुए इजाफे को देखते हुए सरकार तीन लाख की लिमिट को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। संभावना है, चार से पांच लाख तक का ब्याज चार फीसदी की दर से देने का फैसला लिया जा सकता है।

सोलर पंप का बहुपयोगी इस्तेमाल

देश भर में किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी दरों पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग-अलग किलोवॉट के पंप दिए जा रहे हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के लिए भी हो सके। इस पर सरकार भी विचार कर रही है, जिसको लेकर बजट में घोषणा संभव है।

ज्यादा सब्सिडी या टैक्स दरों में कटौती

कृषि उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाई जा रही है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी को हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ दे। जानकार बताते हैं कि सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों को कम कर सकती है या फिर ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला ले सकती है।

स्व-सहायता समूह, कुटीर व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने बैंक अपनाएं सहयोगी प्रवृत्तिः सीएम

भोपाल, जागत गांव हार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्व-सहायता समूह, कुटीर-ग्रामोद्योग तथा मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक सहयोगी प्रवृत्ति अपनाते हुए अपनी गतिविधियों का विस्तार करें। रोजगारमूलक कार्यों के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सभी जिलों में समान रूप से गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। व्यापार-व्यवसाय के साथ जन-कल्याण और आम आदमी की आर्थिक आत्मनिर्भरता से संबंधित कार्यों में बैंकों की ओर से संवदेनशीलता और तत्परता के साथ कार्य अपेक्षित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 189वीं और 190वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को राज्य बैंकर्स समिति ने राज्य शासन द्वारा सर्वजन हिताय बजट प्रस्तुत करने और एक पेड़ मां के नाम वृहद पौधरोपण अभियान के लिए बधाई देते हुए पौध-रोपण में सभी बैंकों के सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एन्युअल क्रेडिट प्लान मध्यप्रदेश 2024-25 पुस्तक का विमोचन भी किया।

उद्योग-व्यापार प्रोत्साहन के लिए आंचलिक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समान विकास के उद्देश्य से उद्योग-व्यापार प्रोत्साहन के लिए आंचलिक स्तर पर गतिविधियां संचालित कर रही है। बैंकर्स इस उद्देश्य से विभिन्न अंचलों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करें। विकास और गरीब कल्याण राज्य सरकार की सवोच्च्च प्राथमिकता है। जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त साहूकारी प्रथा से निकालकर लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार घुमन्तु, अर्धघुमन्तु जनजातियों को ठोस आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें कृषि अथवा व्यवसाय से जोड़ने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जिन 14 स्थानों पर बैंकिंग शाखाएं खोली जाना शेष हैं, वहाँ आवश्यक समन्वय एवं प्रबंध कर समय-सीमा में बैंक सुविधा आरंभ की जाए।

मऊगंज, मैहर, पांदुर्ना आगर-मालवा तथा निवाड़ी में भी आरंभ होंगे ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

बैठक में वर्ष 2023-24 में बैंकों की व्यवसाय वृद्धि, वार्षिक साख योजना, शासकीय योजनाओं की प्रगति पर जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही वित्तीय समावेशन, गैर निष्पादित अस्तियों के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ। बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लगभग सभी जिलों में की गई है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। नए जिले मऊगंज, मैहर और पांदुर्ना और पहले से आगर-मालवा तथा निवाड़ी में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मलय श्रीवास्तव, के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव सहकारिता दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के संचालक जितेन्द्र असाटी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक टीएस जीरा सहित राज्य शासन के अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ग्रीन ऐग परियोजना से मिलेगी खाद्य सुरक्षा

भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के भारत प्रतिनिधि टाकायूकी हॉगीवारा एवं टीम द्वारा गत दिनों एम सेल्वेन्द्रन, सचिव, कृषि से मुलाकात कर ग्रीन ऐग परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कई पहलुओं पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि जैव विविधता प्रबंधन, जलवायु अनुकूलता, भूमि संरक्षण, वन प्रबंधन, पशुपालन व खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ऐग परियोजना संचालित की जा रही है। टाकायूकी ने परियोजना के तहत गतदिनों प्रोजेक्ट क्षेत्र में किए गए भ्रमण को लेकर अपने विचार साझा किए। श्री टाका ने श्री सेल्वेन्द्रन से ग्रीन ऐग परियोजना के माध्यम से क्षेत्र किये जा रहे कार्यों को कवर्जेन्स द्वारा बढ़ावा देने पर विमर्श किया। साथ ही परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों की बेहतर आजीविका के लिए विभिन्न सेक्टर में कार्य करते हुए पशुपालन, मिल्क कलेक्शन सेन्टर, बॉयोगैस प्लांट एवं प्लांटेशन इत्यादी के बारे में चर्चा की।

ज्ञातव्य है कि ग्रीन ऐग परियोजना जिला श्योपुर के ब्लॉक विजयपुर और मुरैना के सबलगढ़ के चिन्हित क्षेत्र में संचालित की जा रही है। उक्त बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारी रविंद्र मोदी, गोपाल सिंह सोलंकी, साथ ही ग्रीन ऐग परियोजना की एन.पी.एम.यू. टीम दिल्ली से मनोज कुमार मिश्रा, एनआरएम स्पेशलिस्ट देवश्री नायक एवं हेमंत सिंह मौजूद थे एवं भोपाल एस.पी.एम.यू. टीम से सुजान सिंह बिमल, श्वेता चौरसिया, मिली मिश्रा, बुशरा खान उपस्थित थीं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)